ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों और उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटन समग्र रूप से किया जाता है और इससे आगे राज्यों में इसके वितरण की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य सरकार की है। 1.4.95 तक बिना पेयजल स्रोत वाली बसावटों की संख्या निम्नानुसार है:—

| राज्य | बिना पेयजल स्रोत वाली बसावटें |
|---|---|
| 1. उत्तर प्रदेश | 19531 |
| 2. बिहार | 21542 |
| 3. पंजाब | 56087 |
| 4. राजस्थान | 15528 |
| 5. हरियाणा | — |
| 6. जम्मू व कश्मीर | 1271 |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 5864 |
| 8. दिल्ली | 1 |

(ख) और (ग) सरकार, राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के भंडार और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता की निगरानी करती है। वस्तुओं की कमी होने पर उनकी आपूर्ति का प्रबंध प्राथमिकता आधार पर किया जाता है। सभी "कवर न की गई बसावटों" में 1997 तक स्वच्छ पेयजल मुहैया कराए जाने की संभावना है।

**बिहार में भारी उद्योगों को स्थापित किया जाना**

504. **श्री राम गोपाल यादव:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार में भारी उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):** (क) से (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान बिहार राज्य में आधारिक स्तर पर भारी उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उद्योग स्थापित करने का निर्णय कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद हेतु उचित बाजार, विद्युत उपार्जन, उचित अवस्थिति, और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता इत्यादि अनेक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बहरहाल बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उपक्रमों के अंतर्गत कुछ केन्द्रीय परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। 100 करोड़ से अधिक लागत वाली ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम 22-3-1995 को संसद के पटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1993-94 के खण्ड-1 के पृष्ठ संख्या 48 से 59 पर दिए गए हैं।

**Functioning of BBUNL**

505. **SHRI MD. SALIM:**
**SHRIMATI CHANDRAKALA PANDEY:**

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to answer to Unstarred Question 2391 given in the Rajya Sabha on the 11th August, 1994 and state:

(a) whether a full-time Chairman and Managing Director has since been posted in Bharat Udyog Nigam Limited (BBUNL) and if not, the action taken so far;

(b) the numbr of functional Directors in position;

(c) the number of Companies under BBUNL referred to BIFR;

(d) whether BBUNL is having composite action plan for revitalising the subsidiaries and if so, whether the same has been submitted as a proposal to BIFR; and

(e) if not, whether there is any purpose of maintaining BBUNL which is failing to coordinate the activities of its subsidiaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir. All efforts are being made to fill-up the vacancy at the earliest.

(b) One.

(c) to (e) Out of the ten subsidiaries of BBUNL, the seven has been referred to BIFR. The revival of these companies has to be based on the strength of each individual PSU BBUNL as the holding company strengthens their synergic bonds